

उत्तर प्रदेश सरकार
नगरीय रोजगार एवं गरीबी
संख्या-972/69-1-2002-4 एल/2001 उन्मूलन
उन्मूलन कार्यक्रम अनुभाग
लखनऊ: दिनांक- 10 अप्रैल, 2002

अधिसूचना

सफाई कर्मचारी नियोजन और शुष्क शौचालय सनिमाण (प्रतियेध) अधिनियम, 1993 (अधिनियम संख्या 4 सन् 1993) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन शक्ति का प्रयोग करे, राज्यपाल, उक्त धारा की उपधारा (2) के अधीन यथा अपेक्षित राज्य सरकार के ऐसा करने के अभिप्राय की अधिसूचना संख्या 2195/69-1-2001-4 (एल) 2001, दिनांक 2 अगस्त, 2001 द्वारा सूचना देने के पश्चात् विनिर्दिष्ट करते हैं कि उत्तर प्रदेश के सम्मूर्ख क्षेत्र में भीतर, जहाँ पर जल प्रवाहित शौचालयों के प्रयोग की पर्याप्त सुविधायें विद्यमान हैं, और जहाँ पर्यावरण और लोक स्वास्थ्य के संरक्षण और सुधार के लिये आवश्यक और समीचीन हैं, दिनांक 10 अप्रैल, 2002 से किसी व्यक्ति को मानव विष्टा को शारीरिक रूप से ढाने के लिये या शुष्क शौचालयों के निर्माण या अनुसरण में, न लगाया जायेगा या न ही इसके लिये नियोजित किया जायेगा या न तो लगाये जाने या नियोजित किये जाने की अनुज्ञा दी जायेगी।

आज्ञा से,
एस. आर. लाखा
सचिव

UTTAR PRADESH SHASAN
Nagariya Rojgar Eevam Garibi
Unmulan Karyakram Anubhag

In pursuance of the provisions of clause (3) of article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 972/69-1-2002-4(L)2001 dated 10th April, 2002.

Notification

No. 989/69-1-2002-4(L) 2001

Dated Lucknow, 10 April, 2002

In exercise of the powers under subsection (1) of section 3 of the Employment of Manual Scavengers and Construction of Dry Latrines (Prohibition) Act, 1993 (Act no. 46 of 1993), the governor, after giving notice of the intention of the State Government so to do by notification no. 2195/69-1-2001-4(L)2001 dated August 2, 2001 as required under sub-section (2) of the said section, is pleased to specify that with effect from 10th April, 2002 no person shall engage in or employ for or permit to be engaged in or employed for manually carrying human excrete or construct or maintain dry latrine within the area of the whole of Uttar Pradesh where adequate facilities for the use of water seal latrines exist and wherein it is necessary and expedient to do so for the protection and improvement of the environment and public health.

By Order,
(S.R. Lakha)
Secretary

उत्तर प्रदेश सरकार
 नगरीय रोजगार एवं गरीबी
 कार्यक्रम अनुभाग १
 संख्या-1049/69-1-02-4 (एल)/2001
 लखनऊ दिनांक 16 अप्रैल, 2002

अधिसूचना विज्ञप्ति संख्या : 972/69-1-2002-4(एल)/2001 दिनांक 10-4-2002 की प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाही हेतु प्रेषित है :

- 1- निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, ३०४० को अंग्रेजी प्रति सहित इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वे कृपया राजपत्र के अगले अंक में उक्त अधिसूचना प्रकाशित कराने का काट करें।
- 2- समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, ३०४० शासन।
- 3- समस्त मण्डलायुक्त, ३०४०।
- 4- समस्त जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला नगरीय विकास अभिकरण, ३०४०।
- 5- सचिव, भारत सरकार, शहरी विकास एवं गरीबी उपशमन मंत्रालय,
नई दिल्ली।
- 6- सचिव, मानवाधिकार आयोग, नई दिल्ली।
- 7- निदेशक, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, ३०४०, लखनऊ को इस निदेश के साथ प्रेषित कि वे उक्त अधिसूचना का व्यापक प्रचार-प्रसार करने का काट करें।
- 8- निदेशक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण, ३०४०।
- 9- महानिदेशक, पुलिस, ३०४०/समस्त पुलिस महानिरीक्षक, ३०४०।
- 10- समस्त बरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, ३०४०।
- 11- समस्त उपाध्यक्ष, विकास प्राधिकरण।
- 12- समस्त मुख्य नगर अधिकारी, नगर निगम/नगर पालिका ३०४०।
- 13- समस्त अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, नगर पंचायत एवं टाउन एरिया।
- 14- आयुक्त, अनुसूचित जाति वित्त विकास निगर, लखनऊ।
- 15- आयुक्त, अनुसूचित जाति एवं जनजाति, ३०४०, लखनऊ।
- 16- समस्त मुख्य विकास अधिकारी, जिला पंचायत अधिकारी, ३०४०।
- 17- समस्त परियोजना निदेशक, जिला नगरीय विकास अभिकरण, ३०४०।
- 18- गार्ड चुक।

आज्ञा से,
 राम किशोर
 अनु सचिव